coconut oil particularly, in Kerala. But I would like to ask the hon. Member to bear in mind the fact that palm oil is imported into India because of the fact that our domestic edible oil production is simply not sufficient to meet the increase in consumption. We are importing palm oil to meet the domestic demand. Palm oil is consumed all over the country. But coconut oil is consumed only in Kerala. And, my own experience is that a large number of consumers in Kerala prefer palm oil to coconut oil.

*284. [The questioner (Shri Mahendra Mohan) was absent. For answer *vide* page 23]

MR. CHAIRMAN: Question No. 285 ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, मुझे एक बात कहनी है।

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आप कृपा करके सुन लीजिए।

श्री सभापति: नहीं। प्लीज।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर पिछले दिनों भी SEZ के मामले पर एक प्रश्न आया था। आपको स्मरण होगा, उस समय भी हम उस पर कोई चर्चा नहीं कर पाए थे।

MR. CHAIRMAN: We can have a discussion. But this is not the time ...(*Interruptions*)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आज भी जिस मैम्बर ने क्वेश्चन दिया है, वे नहीं हैं। श्रीमन्, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही है और यह लग रहा है कि कुछ मिलीभगत है।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: पहले मैच फिक्सिंग होती थी, अब क्या प्रश्न फिक्सिंग भी होने लग गई है?

श्री सभापति: क्वेश्चन 285।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: श्रीमन्, इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में कोई चर्चा न हो सके, सवाल न पूछे जा सकें ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सवाल पूछिए, मगर ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आपको सदन के बाकी सदस्यों के हितों का और अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए और अगर क्वेश्चन देने वाला सदस्य नहीं भी है, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको लेना चाहिए। ये हाऊस की प्रॉपर्टी बन जाता है, अगर प्रश्न रह जाते हैं।

श्री सभापति: अगर प्रश्न देने वाला मैम्बर प्रेजेंट नहीं है तो सवाल पूछा नहीं जा सकता, रिटर्न जवाब मौजूद है।

दिल्ली और मुम्बई के बीच औद्योगिक कारिडोर

*285. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और जापान की साझेदारी से दिल्ली और मुंबई के बीच औद्योगिक कारिडोर बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) दिल्ली और मुम्बई के बीच इस औद्योगिक कारिडोर में किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) सरकार ने इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने अगस्त, 2007 में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) को बनाने के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान किया है। इस परियोजना को विकसित करने में जापान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत गठित एक इण्डो-जापान कार्य बल द्वारा दी गई निविष्टियों का भी उपयोग किया गया।

(ख) डीएमआईसी परियोजना का उद्देश्य चुनिन्दा औद्योगिक नोड्स में बेहतर गुणवत्ता की औद्योगिक अवसंरचना प्रदान करना है। औद्योगिक अवसंरचना में औद्योगिक संपदा, नोलेज हब, कृषि प्रसंस्करण हब, आईटी/आईटीईएस हब, लोजिस्टिक हब तथा भौतिक अवसंरचना (फीडर सड़कें/रेल लाइन, पत्तन, हवाई अड्डें, विद्युत आदि) सम्मिलित होंगे। भारत सरकार द्वारा समग्र निर्देशन, नियोजन तथा अनुमोदन प्रदान करने हेतु 8 केन्द्रीय मंत्रियों तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्रियों के एक शीर्ष मानीटरिंग प्राधिकरण का गठन किया गया है। जहां जरूरी हो, परियोजना के विकास, समन्वय तथा वित्तीयन हेतु भारत सरकार द्वारा 49 प्रतिशत की इक्विटी से दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) नामक कार्पोरेट सत्ता (एंटिटी) की परिकल्पना की गई है। परियोजना का चरण-I दिल्ली-मुम्बई समर्पित रेल फ्रेट कारीडोर के साथ-साथ पूरा किया जाने का कार्यक्रम है।

(ग) सरकार ने परियोजना के चरण-I में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 12 औद्योगिक नोड्स का विकास निम्नानुसार अनुमोदित किया है:—

निवेश क्षेत्र (200 वर्ग कि॰ मी॰ से अधिक)

- उत्तर प्रदेश में दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र;
- हरियाणा में मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र;
- राजस्थान में कुशखेड़ा-भिवाडी-नीमराना निवेश क्षेत्र;
- मध्य प्रदेश में पीतमपुर-धाड-मऊ निवेश क्षेत्र;
- गुजरात में भरूच-दाहेज निवेश क्षेत्र;
- महाराष्ट्र में इगतपुरी-नासिक-सिन्नार निवेश क्षेत्र;

औद्योगिक क्षेत्र (100 कि॰मी॰ से अधिक)

- उत्तर प्रदेश में मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र;
- हरियाणा में फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक क्षेत्र;
- राजस्थान में जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र;
- मध्य प्रदेश में नीमच औद्योगिक क्षेत्र;
- गुजरात में वड़ोदरा-अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र;
- महाराष्ट्र में अलेवाडी/डिघी।

(घ) इन औद्योगिक नोड्स के लिए मास्टर प्लान डीएमआई-सीडीसी द्वारा विकसित की जायेगी। इन मास्टर प्लानों में योजनाएं/अलग-अलग परियोजनाएं बनेगी।

Industrial Corridor between Delhi and Mumbai

†*285. SHRI DATTA MEGHE: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether scheme to build industrial corridor between Delhi and Mumbai with the partnership of India and Japan has been finalised;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, detailed outline thereof;

(c) the areas included in this Industrial Corridor between Delhi and Mumbai; and

(d) the schemes formulated by Government for the development of these areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION, MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ASHWANI KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government of India has granted 'in-principle' approval to the development of Delhi and Mumbai Industrial Corridor (DMIC) in August 2007. Inputs by an Indo-Japan Task Force set up under a MoU with the Government of Japan were also used to developing the Project.

(b) The approach of DMIC project is to provide good quality industrial infrastructure in selected industrial nodes. Industrial infrastructure will include industrial estates, knowledge hubs, agro processing hubs, IT/ITES hubs, logistics hubs and physical infrastructure (feeder roads/rail line, ports, airports, power etc.). An Apex Monitoring Authority has been constituted by the Government of India with 8 Central Ministers and Chief Ministers of UP, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra to provide overall guidance, planning and approvals. A corporate entity "Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) with 49% equity by Government of India is envisaged for project development, co-ordination and financing wherever needed. Phase I of the project is scheduled to be completed in synchronization with Delhi Mumbai Dedicated Rail Freight Corridor."

(c) The Government has approved development of 12 industrial nodes in Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra in the Phase I of the project as below:—

Investment Regions (over 200 square kilometers):

- Dadri-Noida- Ghaziabad Investment Region in Uttar Pradesh;
- Manesar-Bawal Investment Region in Haryana;
- Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Investment Region in Rajasthan;
- Pitampura-Dhar-Mhow Investment Region in Madhya Pradesh;
- Bharuch-Dahej Investment Region in Gujarat;
- Igatpuri-Nashik-Sinnar Investment Region in Maharashtra.

Industrial Areas (over 100 square Kilometers):

- Meerut-Muzaffarnagar Industrial Area in Uttar Pradesh.
- Faridabad-Palwal Industrial Area in Haryana,
- Jaipur-Dausa Industrial Area in Rajasthan,
- Neemach Industrial Area in Madhya Pradesh,
- Vadodara-Ankleshwar Industrial Area in Gujarat,
- Alewadi/Dighi in Maharashtra.

(d) Master Plans for these industrial nodes will be developed by DMICDC. Schemes/ individual projects will come out of these Master Plans.

श्री दत्ता मेघे: सभापति जी, पिछली बार जब जापान के प्रधानमंत्री, Shinzo Abe तीन दिन के लिए भारत आए थे तो यह कहा गया था इस मौके पर कि दिल्ली, मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर पर साझेदारी को कोई अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन तब से इस बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। यह कहा जा रहा है कि 90 अरब डॉलर की यह योजना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस कॉरिडोर को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? पिछले साल जब हमारे प्रधान मंत्री जी जापान गए थे तो सामरिक साझेदारी के बारे में एक जापान के साथ एक सह सहमति बनी थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या यह कार्य अगले वर्ष शुरू हो जाएगा?

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I would like to categorically assure the hon. Member that the in-principle approval of the project corridor has been given to the DMIC. In fact, when the Prime Minister of Japan visited India in August, the agreements were signed and were approved. And I am happy to inform the hon. Member that, according to our estimates, the work will begin early next year and the first phase of the project is likely to be completed by the year 2012. I am also happy to inform the hon. Member that the Government is an advanced stage of short-listing the project management consultants who would be devising various specific schemes and projects that would be culled out of the master plans that are now in the process of being formulated. In the meanwhile, a three-tier structure has been established. One is the apex monitoring committee, which is chaired by the Finance Minister of India and it has eight Central Cabinet Ministers on it, six Chief Ministers of the concerned States through which the project will be executed. On the operational side, we are incorporating a company known as the Delhi-Mumbai Indistrial Corridor Corporation which will oversee the implementation of the various projects in association with the project management consultant. Sir, this project is a national project, the only project of its kind. It is estimated, as of now, that when completed, it would involve a capital outlay of close to a hundred billion dollars, about 90 billion dollars to be precise, or, Rs.3,60,000 crores. It would quadruple the employment and increase exports manifold and, that is why, it is receiving the top priority from the Government.

श्री दत्ता मेघे: सर मेरा दूसरा क्वेशन है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दिल्ली से मुंबई के बीच बनने वाली औद्योगिक कारिडोर में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रों में यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से होकर यह कारिडोर बनाया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि नागपुर हमारे देश के मध्य में स्थित है और इसका संदर्भ विदर्भ के पिछड़े क्षेत्रों से है, इसलिए क्या नागपुर और विदर्भ के क्षेत्रों को भी दिल्ली और मुंबई के बीच बनने वाली औद्योगिक कारिडोर में शामिल किया जाएगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, this project has been conceptualised along the alignment of the Delhi-Mumbai freight corridor and, therefore, Sir, in the first instance, it is going to cross through six States which are Uttar Pradesh, Haryana , Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Within these States, the nodes have been identified. I would like to inform the hon. Member that amongst the nodes that have been identified at this stage, they have the Dadri-Noida-Gaziabad node, Maneswar-Bawal investment region, Kurukshetra-Bhiwadi, Pritampura- Dhau in Madhya Pradesh, Bharuch-Dahej in Gujarat, Igatpuri-Nasik. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please. Let the ...*(Interruptions)*

श्री दत्ता मेघे: इसमें मध्य प्रदेश तक जा रहे हैं ...(**व्यवधान**)... नागपुर इसमें एड नहीं है ...(**व्यवधान**)... मैं नागपुर की बात कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

SHRI ASHWANI KUMAR; Sir, I am reading it out. महाराष्ट्र में इगातपुरी-नासिक-सिनार and also Alewadi and Dighe in Maharashra, as far as the industrial region is concerned. Sir, the difficulty is that for this corridor to be viable and serve its purpose, it has to be along the alignment. However, I have said that representations are being received; we have an open mind. If technically feasible, we will certainly involve other areas as well *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please. Your supplementaries are over.

श्री दत्ता मेघे: सर,मैं इतना बड़ा क्वेशन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नागपुर इसमें एड नहीं है, नजदीक से जा रहे हैं तो नागपुर में हो, मेरा क्वेशन पूछने का अर्थ ही यही है।

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, मैं मानता हूं कि आज की जो स्थिति है उसमें नागपुर included नहीं है, क्योंकि यह समझा गया है कि यह जो alignment है, उससे बहुत पीछे है, मगर जैसा मैंने आपको आश्वस्त किया है अगर technically feasible होगा, हमारे पास representations आ रहे हैं, इसको हम consider करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Santosh Bagrodia.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, the hon. Minister has mentioned twice; ones in the written reply and then again in reply to the earlier supplementary that Phase-I of the project is scheduled to be completed in synchronisation with Delhi- Mumbai Dedicated Rail Freight Corridor. Now, Sir, when we acquire land for Railways, that is a different situation. I would like to know from the hon. Minister whether we are acquiring the same land which is actually acquired for railways, and now it will be used for industrialisation. If that is so, is it legally and technically right because we will be misguiding the people of our nation that we have acquired it for a purpose and then we are using it for a different purpose. If not, who will acquire land? Sir, acquisition of land is a very big issue in the country today. Who will own this land? I am asking this question because 49 per cent is with the Government, I mean, this is all vague. I would like the hon. Minister to please clarify as to who is going to control all this land along with the Delhi-Mumbai Dedicated Rail Freight Corridor.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I would like to inform the hon. Member that as far as land acquisition is concerned, the land that is specifically acquired for establishing the Delhi-Mumbai Rail Freight Corridor is one part of the story. The Delhi-Mumbai Industrial Corridor is going to come up in an area of about 150 to 200 square kilometres on either side of the track, which would be a subject matter of separate acquisition. Now, Sir, the point that is important, and what the hon. Member asked is, what would be the ownership of the land. Sir, the ownership of the land will initially be vested in the acquiring authority, which, in the initial stages, could be the DMICDC. Although the government has directly 49 per cent in it, but the rest of the 51 per cent is going to be disbursed, Sir, that it will be with the FIIs, it will be with infrastructure development organisation like the IDFC, which again are primarily controlled by the Government. So, depending upon the need, depending upon the extent of the acquisition required, Sir, the special purpose vehicles and the DMICDC will actually do that. But all of this, at this stage, is in a preliminary stage. As we go along the path of execution, we will find the best, the most appropriate and certainly the legal mechanisms to go in for the acquisition so that these are not stopped.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I would like to know from the hon. Minister whether it will be Government-controlled or private-controlled.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, as of now, the equity structure of the DMICDC says that 49 per cent will be directly held by the Government. The rest of the equity structure will be such that institutions in which the Government also has majority control will be major participants. The exact contours of the equity structure have not been worked out.

SHRI SYED AZEEZ PASHA: Sir, I was interested in the earlier question, not in this one.

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, this Delhi-Mumbai industrial Corridor is going to be an important scheme of the Government, and the question asked by Shri Datta Meghe is an important one. In Maharashtra, the people of Vidarbha always feel that it is a backward area, there is no development in the area, and the people of Vidarbha have asked for a separate State also. Therefore, it becomes absolutely necessary that Vidarbha, which includes Nagpur also, becomes a part of this particular scheme. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of Maharashtra has sent a proposal to the Government of India to include this particular area in this corridor. I would also like to know from the hon. Minister whether he would like to call the Members of Parliament from Vidarbha for a discussion in connection with this corridor.

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, I respect the sentiment of hon. Joshiji. As far as development of Vidarbha region is concerned, we are second to none in seeking to promote the all-round development of Vidarbha region. Sir, we have received three representations so far from the Chief Ministers of Tamil Nadu, from Punjab and from Gujarat. Sir, as far as I am aware, as on date, there is no proposal received specifically for getting the corridor extended to cover Vidarbha region, Nagpur in particular. But, as I said, Sir, we have an open mind. If technically feasible, and if representations are received, we would, certainly, look at it with an open mind. The only difficulty, Sir, that we face, as far as including more and more areas in this system is concerned, is that for it to be viable, it must be contiguous or close to the Rail Freight alignment. That is the only technical requirement. Subject to that, we have an open mind. Sir, we would be very happy to invite Members of Parliament from the region at any time and I would be available at your convenience to meet and discuss things.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Sir, I would like to know from the hon. Minister the time-frame within which the Master Plans would be ready, since he has not given the time-frame. In part (b) of the answer he has talked about the infrastructure of airports and power. Maharashtra already has a deficit of 5,500 MWs today. How are you going to address this problem?

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, as far as the Master Plan's time-frame is concerned, we are still at the stage of short-listing and hiring a project management consultant who will then be working with the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Corporation Management to find out what are the best linkages that could be identified and then the work would start. As far as linkages and connectivity are concerned, the answer is in the context of what will be the contribution of the Central Government. We have said that the State Governments, the Central Government, the stake-holders, the developers, the Special Purpose Vehicle would all pool in their resources. The Central Government would assist in creating the necessary physical infrastructure consisting of rail linkages, ports, power, etc. etc.

As far as the availability of certain infrastructure in Maharashtra is concerned, none doubts that. I said earlier and I would like to repeat it, that as far as including more

areas in this project is concerned, that is a function of its viability and synchronisation with the alignment of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Corporation.

*286. [The questioner(s) (Shri Dara Singh and Shri Ramdas Agarwal) were absent. For answer *vide* page 23]

*287. [The questioner (Shrimati Hema Malini) was absent. For answer *vide* page 24]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धन का आबंटन

*288. **श्री सुरेन्द्र लाठ:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत कुल कितने धन का प्रावधान किया गया तथा कुल कितना धन उसमें से आबंटित किया गया;

(ख) राज्य सरकारों ने मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि में से कुल कितने धन का उपयोग किया;

(ग) क्या इन योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय इनका समय-समय पर मूल्यांकन करता है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में इन योजनाओं को सही ढंग से लागू न किये जाने की कोई रिपोर्ट सरकार को मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ड.) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण अवसंरचना के सृजन तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्व-रोजगार उपलब्ध कराती है जबकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा और पोषक पोषाहार मुहैया कराया जा सके और स्थाई सामुदायिक परिसम्पत्तियां तथा अवसंरचना का सृजन किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) इस समय 330 जिलों में कार्यान्वित है तथा 1.4.2008 से देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी जिसका उद्देश्य शारीरिक कार्य करने वाले प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार देना है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) बेघरों को घर मुहैया कराती है। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का उद्देश्य सड़क संपर्कता है, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना और ग्रामीण सुविधाओं का विकास करना है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं जो वाटरशैड आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं। भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना और भू अभिलेखों को अद्यतन बनाना (एसआरए तथा यूएलआर) की योजनाएं भी कार्यान्वित की जाती हैं। 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मंत्रालय की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटन (बजट अनुमान) क्रमश: 15998.40 करोड़ रुपये, 24480.00 करोड़ रुपये तथा 31443.62 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के दौरान वास्तविक रिलीजें 18166.83 करोड़ रुपये, 27488.83 करोड़ रुपये तथा 30981.94 करोड़ रुपये थीं।

2. पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07) के दौरान मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं अर्थात् एसजीआरवाई, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), एनआरईजीएस, एसजीएसवाई, आईएवाई, पीएमजीएसवाई, आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी, डीडीपी, सीएलआर, एसआरए तथा यूएलआर, एआरडब्ल्यूएसपी तथा टीएससी के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों तथा कुल उपलब्ध निधियों (अथशेष, केन्द्रीय रिलीजों और राज्य रिलीजों तथा विविध प्राप्तियों) में से उपयोग की गई राशि के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे **देखिए**)

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के प्रभाव का जायजा लेने और निचले स्तर पर कार्यान्वयन में कमियों का पता